MECL, HCL (Hindustan Copper Ltd.) has opened Malanjkhand Mine. HCL is also developing a mine at Banwas in Khetri Copper belt which is a result of discovery made by MECL. Proving of continuity of ore bodies below 'O' MRL (Mean Reduced Level) in Madan Khundan Mine of Khetri Copper belt would enable HCL to increase the depth of a mine.

Inventory of Products in the Stocks of NALCO

3101. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Aluminium Co. Ltd. has built up an alarming inventory of products in their stocks where crores of rupees are held up as a result thereof;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps Government have taken or propose to take to lessen the inventory?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) No, Sir. M/s. National Aluminium Company Limited (NALCO) had inventory of about 750 MT as on 31.3.1997 which is less than 2 days' production.

(c) Does not arise.

Rehabilitation Package for Workers of Bharat Gold Mines

3102. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of MINES be pleased to refer to the answer to Starred Question 313 given in the Rajya Sabha on the 17th March, 1997 and state:

(a) the reasons for not taking any decision on tender quotations received for treatment of huge tailings in Bharat Gold Mines Ltd., Kolar;

(b) whether the evaluation report of these quotations was placed ever before BIFR;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that BIFR has given its final decision for closing Bharat Gold Mines;

(e) if so, the number of workers likely to lose job; and

(f) the details of rehabilitation package, if any, prepared for such workers?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) The Bharat Gold Mines Limited (BGML) floated global tenders in July, 1994 for exploration/exploitation of gold in the areas held under lease by BGML and for setting up of a project for recovery of gold through treatment of tailings. However, taking into account the financial benefits accruing to BGML, it was decided that it will be more beneficial for the Company to set up the project for extraction of gold from treatment of tailings on its own rather than through Joint Venture route.

(b) and (c) Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) appointed M/s. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) as the Operating Agency (OA) for BGML. The tenders were evaluated in consultation with ICICI. The result of evalutation was reported to BIFR.

(d) to (f) No, Sir, BIFR issued winding up notice vide its order dated 14.11.96 against which BGML appealed before Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR). has quashed this order and remitted the matter to BIFR.

खनन कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना

3103. श्री राम जेठमलानी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में खानों में खनन कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिए जाने के बाद से निजी क्षेत्र की फर्मों से कई पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी पेशकश प्राप्त हुई हैं;

(ग) उनमें से कितनी पेशकश स्वीकार हो गई है; और

(घ) क्या सरकार ने इन पेशकशों की स्वीकृति के लिए कोई सर्वमान्य पारदर्शी मानदण्ड निर्धारित किए है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) खनन संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957

के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। देश में खनन कार्य ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1994-95 के अन्त तक कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में से जो गैर परमाणु और गैर-ईंधन खनिजों और गौण खनिजों से इतर अन्य खनिजों का उत्पादन कर रही है, 316 निजी क्षेत्र में थीं। खान-और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार खनन अधिकार केवल किसी भारतीय राष्ट्रीक या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित कंपनी को ही दिये जा सकते हैं। लेकिन प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के लिए कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रदान नहीं किया जायेगा।

गुजरात में खनिजों की उपलब्धता का पता लगाने हेतु कार्य-योजना

3104 **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य में खनिजों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक कार्य योजना पर विचार किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ एक कार्य बल का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य बल की क्या-क्या उपलब्धि रही है; और

(घ) वर्तमान कार्य योजना में अंतर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गुजरात सहित देश के खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए खनिज अन्वेषण और इससे संबंधित अन्य कार्य जारी कार्यक्रमों के रूप में कर रहा है।

(ख) भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य दल गठित नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Imports of Phosphates from Nauru Island

3105. SHRI SURINDER KUAMR SINGLA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether India still imports phosphates from the Nauru Island in the Pacific;

(b) if so, the unit cost of phosphate being imported and how does it compare with the indegenous phosphates;

(c) for how many years more do we have have lease of phosphate mines, if any in Nauru; and

(d) the steps being taken to bring self sufficiency in phospates?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा गुजरात में खनन

3106 **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने गुजरात के कुछ जिलों में खनन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या किसी परियोजना का कार्य रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(च) क्या निगम ने कुछ परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) निगम को अब तक हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) किसी परियोजना के गुजरात राज्य में किसी निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) विगत 3 वर्षों के दौरान मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अर्जित कर से पूर्व लाभों का ब्यौरा